शुक्रवार
24 जुलाई 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 181
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

लाठियों के खिलाफ 'खाकी' की बगावत!

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। दिल्ली के जंतर-मंतर में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे आंदोलन को भावनात्मक

◆जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के बीच उत्तराखंड पुलिसकर्मी ने लिया फैसला
◆मंच पर बैज रखकर जवान बोला- मैं युवाओं के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता
◆पुलिस कर्मी बोला-छात्रों पर लाठी नहीं चला सकता, भावुक संबोधन से गूंजा पंडाल
◆जंतर-मंतर आंदोलन के मंच से पुलिस के जवान ने किया इस्तीफा देने का ऐलान

मोड़ दे दिया। उत्तराखंड पुलिस के एक जवान, शेर सिंह ने मंच पर पहुंचकर अपनी वर्दी का बैज उतार दिया और सार्वजनिक रूप से अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। जवान ने कहा कि वह उन छात्रों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, जो अपने भविष्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में चल रहे इस वीडियो और उसमें कही बातों की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि यह जवान निलंबित है और शायद लंबे समय से अनुपस्थित चल रहा है। जैसे ही पुलिसकर्मी ने मंच से अपना बैज उतारा, पूरा पंडाल तालियों और नारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कई छात्र भावुक हो गए, जबकि मंच पर मौजूद आंदोलन के नेताओं ने इसे युवाओं के संघर्ष के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक बताया।

मंच से बोलते हुए पुलिस जवान ने कहा कि उसने वर्दी पहनते समय संविधान की रक्षा करने और जनता की सेवा करने की शपथ ली थी। लेकिन जब देश के युवा अपने अधिकारों की मांग कर रहे हों और उनके साथ बल प्रयोग हो, तो उसका अंतर्मन उसे चुप रहने की अनुमति नहीं देता। उन्होंने कहा कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उनका कहना था कि पुलिस की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं की आवाज को दबाना उचित नहीं माना जा सकता।

पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा। देश के विभिन्न राज्यों से युवा, सामाजिक संगठन और कई जनप्रतिनिधि भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। हाल के दिनों में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज की घटनाओं ने इस आंदोलन को और अधिक चर्चा में ला दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

उत्तराखंड पुलिस के जवान द्वारा मंच से पुलिस कर्मी के इस्तीफा देने की घोषणा को आंदोलन में मौजूद युवाओं ने विशेष महत्व दिया। छात्रों का कहना था कि यह केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं, बल्कि उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है जिसे देश का युवा महसूस कर रहा है। जवान ने अपने संबोधन में उत्तराखंड के युवाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि रोजगार और पारदर्शी भर्ती हर युवा का अधिकार है। उन्होंने अपील की कि सरकार युवाओं की आवाज को विरोध नहीं, बल्कि सुझाव के रूप में सुने।

हालांकि उत्तराखंड पुलिस के जवान

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

गुलदार की खाल सहित तस्कर गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

पौड़ी। गुलदार का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी करने की फिराक में जुटे एक वन्य जीव तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से पुलिस ने गुलदार की खाल बरामद की है। आरोपी ने गुलदार को दो वर्ष पहले शिकार किया था। जिसकी खाल को वह इन दिनो हरियाणा में बेचने की फिराक में था।

जानकारी के अनुसार बीते रोज थाना सतपुली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम पोखरी, दुधारखाल में एक व्यक्ति के पास गुलदार की खाल है, जिसे बेचने के लिए वह आगामी दिनों में हरियाणा ले जाने की तैयारी कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए ग्राम पोखरी में दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति संदीप कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर तलाशी ली गई। इम दौरान

संदिग्ध व्यक्ति संदीप कुमार धस्माना निवासी ग्राम पोखरी, सतपुली के घर में एक टिन के बॉक्स से गुलदार की खाल बरामद की गई।

आरोपी द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व जंगल में फंदा लगाकर गुलदार का शिकार किया था तथा उसकी खाल निकालकर सुखाकर अपने पास रखी थी, सही खरीदार की तलाश में वह खाल को लंबे समय से छिपाकर रखे हुए था और अब उसे बेचने की योजना बना रहा था। गुलदार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित वन्यजीव की श्रेणी में आता है। ऐसे संरक्षित वन्यजीव का शिकार करना, उसकी खाल रखना अथवा उसका व्यापार करना गंभीर एवं दंडनीय अपराध है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

दून वैली मेल

संपादकीय

अनशन खत्म, अब वादे की परीक्षा

लोकतंत्र में किसी आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता केवल यह नहीं होती कि वह सुर्खियां बटोर ले, बल्कि यह होती है कि वह सत्ता को संवाद की मेज तक आने के लिए विवश कर दे। जंतर-मंतर से शुरू होकर अस्पताल तक पहुंचे सोनम वांगचुक के अनशन का समाप्त होना इसी अर्थ में राहत की खबर है। यह केवल एक व्यक्ति की भूख-हड़ताल का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे टकराव को विराम है जो लंबा खिंचता तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर सकता था। लेकिन असली प्रश्न अब शुरू होता है। अनशन टूट गया है, क्या सरकार अपने आश्वासनों पर खरी उतरेगी? लोकतंत्र में आंदोलनों का सम्मान केवल उनकी समाप्ति से नहीं, बल्कि उनसे निकले निष्कर्षों के ईमानदार क्रियान्वयन से होता है। यदि आश्वासन केवल तत्काल संकट टालने का माध्यम बन जाएं, तो जनता का विश्वास केवल सरकार से नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भी कमजोर पड़ता है। इसी समय देश का दूसरा बड़ा प्रश्न भी सामने है पेपर लीक। पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लगातार प्रश्न उठे हैं। लाखों युवाओं ने वर्षों की मेहनत की, लेकिन कुछ संगठित गिरोहों ने परीक्षा प्रणाली को कारोबार बना दिया। यह केवल अपराध नहीं, युवाओं के भविष्य पर हमला है। इसलिए यदि संसद पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कानून की कठोरता तभी सार्थक होगी, जब जांच एजेंसियां निष्पक्ष हों, मुकदमे समयबद्ध हों और दोषियों को शीघ्र दंड मिले। केवल नए कानून बना देने से समस्या समाप्त नहीं होती उनका निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन ही व्यवस्था में भरोसा लौटाता है। इसके साथ ही एक और बुनियादी सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में छात्र आंदोलन कोई अपराध नहीं हैं। असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। यदि छात्र अपने भविष्य, शिक्षा व्यवस्था या रोजगार के सवाल पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराते हैं, तो राज्य का दायित्व उन्हें सुनना है, न कि उन्हें अपराधी की तरह देखना। पुलिस कार्रवाई अंतिम विकल्प हो सकती है, पहला नहीं। किसी भी लोकतंत्र का आत्मविश्वास इस बात से मापा जाता है कि वह आलोचना को कितनी सहजता से स्वीकार करता है। हालांकि इस सिद्धांत का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आंदोलन की आड़ में यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, हिंसा की जाती है, पुलिस पर हमला होता है या अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है, तो उसे लोकतांत्रिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सुनियोजित उपद्रव के बीच स्पष्ट अंतर करना होगा। जो लोग वास्तविक जनआंदोलनों की आड़ लेकर हिंसा, तोड़फोड़ या राजनीतिक लाभ के लिए अराजकता फैलाते हैं, वह किसी भी जनसंघर्ष की नैतिक शक्ति को कमजोर करते हैं। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल, लोकतंत्र दो समानांतर जिम्मेदारियों पर चलता है। पहली, सरकार की जिम्मेदारी कि वह नागरिकों की बात सुने, संवाद करे और वादों को निभाए। दूसरी, आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी कि उनका विरोध संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर रहे। जब इनमें से कोई एक पक्ष अपनी सीमा लांघता है, तब लोकतंत्र में अविश्वास बढ़ता है। सोनम वांगचुक के अनशन की समाप्ति इसीलिए केवल राहत का क्षण नहीं, बल्कि एक अवसर भी है। यह अवसर सरकार के लिए है कि वह यह साबित करे कि संवाद केवल संकट प्रबंधन का औजार नहीं, शासन की स्थायी संस्कृति है। यह अवसर संसद के लिए भी है कि वह परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने वाले कानूनों पर गंभीरता से विचार करे। और यह अवसर समाज के लिए भी है कि वह शांतिपूर्ण आंदोलनों और हिंसक भीड़तंत्र के बीच फर्क करना सीखे। लोकतंत्र में सरकार की ताकत विरोध को दबाने से नहीं, बल्कि उसे सुनकर समाधान निकालने से बढ़ती है। उसी तरह किसी आंदोलन की नैतिक शक्ति नारे या भीड़ से नहीं, बल्कि उसके अनुशासन और उद्देश्य की स्पष्टता से बनती है। अब जब अनशन समाप्त हो चुका है, तो देश की निगाहें सरकार पर हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा व्रत भूख का नहीं, विश्वास निभाने का होता है। वही विश्वास इस समय सरकार की सबसे कठिन, लेकिन सबसे आवश्यक अग्नि परीक्षा है।

स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में यातायात पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान

हमाग्रे संवाददाता

हरिद्वार। महापौर, नगर निगम रुड़की अनीता अग्रवाल के नेतृत्व में आज आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में यातायात पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए रक्तदान किया। इस अवसर पर अपर यातायात उपनिरीक्षक (एडिशनल टीएसआई) मनोज कुमार, अपर यातायात उपनिरीक्षक (एडिशनल टीएसआई) प्रवीण कुमार तथा कांस्टेबल लवकेश मौर्य ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रेरणादायी संदेश दिया। रक्तदान के माध्यम से पुलिस कर्मियों ने यह संदेश दिया कि "रक्तदान महादान" है और एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही सभी नागरिकों से भी समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान कर समाजहित में योगदान देने की अपील की गई।

आधी रात पीएम का 'मास्टरस्ट्रोक'

◆पेपर लीक को बताया युवाओं के सपनों पर हमला, कैबिनेट के बड़े फैसले का ऐलान
◆भारी दबाव के बीच पीएम का छात्रों के नाम आधी रात जारी किया विशेष वीडियो संदेश
◆प्रधानमंत्री मोदी बोले-युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली। देशभर में पेपर लीक को लेकर जारी छात्र आंदोलनों, बढ़ते राजनीतिक दबाव और परीक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात छात्रों के नाम एक विशेष वीडियो संदेश जारी कर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक केवल एक अपराध नहीं, बल्कि देश के युवाओं के सपनों पर हमला है, इसलिए केंद्र सरकार की कैबिनेट इस मुद्दे पर सख्त और व्यापक फैसला लेने जा रही है। प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय आया है, जब देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन जारी हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में विफल रहने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों युवा वर्षों तक कठिन परिश्रम करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में यदि कुछ संगठित गिरोह प्रश्नपत्र लीक कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय को केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास और देश के भविष्य से जुड़ा विषय मानती है। इसी कारण कैबिनेट स्तर पर व्यापक चर्चा कर कठोर निर्णय लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार परीक्षा सुरक्षा से जुड़े कानूनों, तकनीकी निगरानी, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और पेपर लीक मामलों में त्वरित कार्रवाई जैसे मुद्दों पर नए कदम उठा सकती है।

हालांकि सरकार ने अभी प्रस्तावित फैसलों का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान ने संकेत दे दिया है कि इस मुद्दे को शीर्ष स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद कई राज्यों में छात्र संगठनों के प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ऐसा तंत्र चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक न हो। युवाओं का कहना है कि वर्षों की तैयारी, आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक दबाव के बाद यदि परीक्षा रद्द हो जाती है, तो उसकी भरपाई केवल दोबारा परीक्षा कराने से नहीं होती।

प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का स्वागत है, लेकिन जनता अब घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस परिणाम देखना चाहती है। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में गंभीर है तो बड़े नेटवर्क का खुलासा, समयबद्ध जांच, दोषियों की शीघ्र सजा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। प्रधानमंत्री का आधी रात का वीडियो संदेश केवल प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि युवाओं तक सीधे पहुंचने की राजनीतिक कोशिश भी है। हाल के दिनों में रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर युवाओं की नाराजगी खुलकर सामने आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का सीधे छात्रों को संबोधित करना इस संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को चुनावी बहस नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है।

पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून, तेज जांच और सख्त कार्रवाई की बातें पहले भी कई बार कही गई हैं। इस बार अंतर यह है कि युवाओं का धैर्य पहले से कम और अपेक्षाएं पहले से अधिक हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है। अब निगाहें कैबिनेट के फैसले पर हैं। क्योंकि देश के करोड़ों अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सरकार ने क्या कहा, बल्कि यह है कि सरकार क्या करेगी।

'दावे' बेमिसाल पर कटघरे में 'कंट्रोल'

◆यूटीयू पेपर लीक से लेकर बदरी-केदार मंदिरों के चढ़ावे तक
◆सरकार के दावों पर उठते सवालों को विपक्ष बना रहा हथियार
◆विकास की पटकथा पर भारी पड़ रहे हैं तीन सुलगते सवाल

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी शंखनाद अभी औपचारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन मुद्दों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष विकास, निवेश, चारधाम आल वेदर रोड, समान नागरिक संहिता, धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ऐसे मुद्दों की तलाश में हैं, जो सरकार की विश्वसनीयता पर सीधे सवाल खड़े करें। ऐसे में तीन मुद्दे लगातार राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं यूटीयू पेपर लीक का मामला, बदरी-केदार मंदिरों के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल। इन तीनों मुद्दों की प्रकृति अलग है, लेकिन विपक्ष इन्हें एक ही राजनीतिक संदेश में पिरोने की कोशिश कर रहा है सरकार बड़े दावे करती है, लेकिन व्यवस्था पर नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है।

उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाला युवा पहले ही सीमित अवसरों से जूझ रहा है। ऐसे में जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो उसका असर केवल अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हजारों परिवारों तक पहुंचता है। यूटीयू पेपर लीक का मामला इसी कारण राजनीतिक महत्व हासिल कर चुका है। विपक्ष का आरोप है कि यदि परीक्षा प्रणाली सुरक्षित नहीं है तो युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? सरकार का पक्ष है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए लगातार पूछ रहा है जब दावे इतने बड़े थे तो लीक हुआ कैसे? यही सवाल अब गांवों तक पहुंच चुका है।

उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। बदरीनाथ और केदारनाथ जैसे धामों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा केवल आर्थिक विषय नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक भी है। चढ़ावे से जुड़े विवादों और अनियमितताओं के आरोपों ने विपक्ष को सरकार को घेरने का नया अवसर दिया है। सरकार ने जांच, कार्रवाई और जवाबदेही की बात कही है। लेकिन विपक्ष इसे यह कहकर जनता के बीच ले जा रहा है कि जब भगवान का चढ़ावा सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? यह राजनीतिक नारा भले हो, लेकिन चुनावी सभाओं में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है।

भाजपा इन आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताते हुए विकास कार्यों को अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही है। पार्टी का दावा है कि पिछले वर्षों में सड़क, स्वास्थ्य, रेल, चारधाम परियोजनाओं, निवेश और धार्मिक पर्यटन में अभूतपूर्व काम हुआ है। भाजपा का मानना है कि जनता चुनाव में आरोप नहीं, विकास देखेगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विकास और जवाबदेही दोनों अलग-अलग विषय नहीं हैं। जनता अब यह भी देखना चाहती है कि यदि कोई गड़बड़ी होती है तो सरकार कितनी तेजी और पारदर्शिता से कार्रवाई करती है।

कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि अलग-अलग घटनाओं को जोड़कर सरकार के खिलाफ एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जाए। पेपर लीक, बेरोजगारी, पलायन, मंदिरों के चढ़ावे, महंगाई और प्रशासनिक फैसलों को जोड़कर कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि राज्य में जवाबदेही कमजोर हुई है। हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौती भी कम नहीं है। उसे केवल सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर वह परीक्षा प्रणाली, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन और प्रशासनिक पारदर्शिता में क्या बदलाव करेगी।

उत्तराखंड के चुनाव में हमेशा सैनिक, किसान, महिला मतदाता और क्षेत्रीय संतुलन की चर्चा होती रही है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवा और उनके परिवार चुनावी विमर्श को

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

नगर निगम ने आयोजित किया स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता दिवस

संवाददाता

देहरादून। नगर निगम द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान के दौरान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता दिवस का आयोजन किया। यहां नगर निगम द्वारा 20 जुलाई से 25 जुलाई तक 'स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान' संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यालयों में 'स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता दिवस' आयोजित किया गया। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे के निर्देशनानुसार समस्त मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक ने अपने-अपने आवंटित विद्यालयों में अभियान का संचालन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोने की सही विधि डायरिया एवं मच्छरजनित रोगों की रोकथाम तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित स्वच्छता बनाए रखने तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाव के प्रभावी उपायों, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने तथा जलजनित एवं मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की गई। विद्यालयों में आयोजित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया। नगर निगम देहरादून द्वारा अभियान के अंतर्गत आगामी दिनों में भी विभिन्न गतिविधियों एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित देहरादून के निर्माण के उद्देश्य को साकार किया जा सके।

फरार चल रहा ईनामी गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। धोखाधड़ी मामले में 2025 से फरार चल रहे 5 हजार रूपये के ईनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार थाना सिड़कुल में धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एक मुकदमें में विकास कुमार बीते वर्ष से लगातार फरार चल रहा था व रहने के ठिकाने बदल-बदल कर पुलिस को गुमराह कर रहा था। आरोपी के लगातार फरार रहने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा उसकी गिरफ्तारी हेतु 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। अपने प्रयास जारी रखते हुए पुलिस टीम ने न्यायालय से गैर जमानतीय वारण्ट हासिल कर फरार ईनामी को आखिरकार बीती रात एएमसी लकड़ी फैक्ट्री मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जिसे आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

पर्यावरण मित्रों धरना पांचवे दिन भी जारी रहा

संवाददाता

देहरादून। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले देहरादून नगर निगम के पर्यावरण मित्रों ने पांचवें दिन भी धरना दिया। आज यहां राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले देहरादून नगर निगम के पर्यावरण मित्रों ने पांचवें दिन भी धरना दिया। धरने का नेतृत्व राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष/ संरक्षक चौधरी नरेश वैध, यूनियन के देहरादून नगर निगम शाखा अध्यक्ष सुनील कुमार उर्फ सोनू खैरवाल, यूनियन के सचिव धीरज भारती ने नेतृत्व किया। सोनू खैरवाल ने कहा कि धरना प्रदर्शन हाथों में काली पट्टी बांधकर रोष प्रकट करेंगे और सरकार एक सप्ताह के अंतर्गत मांगो पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो या शासनादेश जारी नहीं करती तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन सभी पर्यावरण मित्रों को लेकर कार्य बहिष्कार करेंगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार और शासन प्रशासन की होगी। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नरेश वैध ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पूरे उत्तराखंड प्रदेश की स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का सहयोग लेकर प्रदेश स्तर पर हड़ताल कराई जाएगी। धरने पर बैठने वालों में मुख्य रूप से यूनियन के उपाध्यक्ष विनोद कुमार देहरादून महिला विंग की अध्यक्ष आरती और सामान्य कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, सचिव योगेश आनंद, अम्रुदीन, अरुण कुमार, शिवानी, सोहनलाल, सोमू सेलवान, मुकेश कुमार, सावित्री देवी, अनीता, तेजपाल, पप्पू, जीवन, प्रकाश, सचिन, रोहित कुमार, आदि कर्मचारी पर्यावरण मित्र उपस्थित रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

'अब हल्या, हल और बैल भी गुम'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। कभी पहाड़ के गांवों की सुबह बैलों के गले में बंधे खांखरे की मधुर आवाज से होती थी। खेतों में हल चलता था, महिलाएं रोपाई के गीत गाती थीं और गोठ में बंधी गाय-भैंस गांव की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थीं। गांव का वह परिवार सबसे संपन्न माना जाता था, जिसके पास मजबूत बैलों की जोड़ी होती थी। बैल सिर्फ खेती का साधन नहीं, बल्कि गांव की प्रतिष्ठा, आत्मनिर्भरता और मेहनतकश जीवन का प्रतीक थे। आज वही पहाड़ एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां कई गांवों में बैलों की आखिरी जोड़ी भी गांव छोड़ने को मजबूर है।

पिछले ढाई-तीन दशकों में पहाड़ का ग्रामीण जीवन तेजी से बदला है। शिक्षा, रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में युवाओं का पलायन हुआ। गांवों में बुजुर्ग और महिलाएं रह गईं। खेती श्रम मांगती है, पशुपालन चौबीस घंटे की जिम्मेदारी है। जब खेत जोतने वाले हाथ ही कम पड़ गए तो बैलों की जरूरत भी खत्म होती चली गई। पहले बैल बिके, फिर गाय-भैंसें कम हुईं और अब अधिकांश गांवों के गोठ खाली पड़े हैं।

पहाड़ में खेती छोड़ने का सबसे बड़ा प्रमाण अब खेतों में दिखने लगा है। जिन खेतों में कभी धान, मंडुवा, झंगोरा, गेहूं और राजमा की फसलें लहलहाती थीं, वहां आज झाड़ियां, चीड़ के पौधे और जंगली वनस्पति उग आई है। वर्षों से बिना जोते खेत धीरे-धीरे जंगल में बदल रहे हैं। इसके साथ ही जंगली जानवरों का आतंक भी बढ़ा है। बंदर, जंगली सूअर, साही और अन्य वन्यजीव बची-खुची खेती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में खेती करने की इच्छा रखने वाले किसान भी हतोत्साहित हो रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले परिवार अपनी जरूरत का अधिकांश अनाज खुद पैदा करता था। खेती जीवन का आधार थी। अब सरकारी राशन योजनाओं, बाजार तक आसान पहुंच और रोजगार के नए विकल्पों ने ग्रामीण जीवन की प्राथमिकताएं बदल दी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने गरीब परिवारों को राहत जरूर दी, लेकिन कई क्षेत्रों में खेती पर निर्भरता भी कम

◆रोपाई के मंगल गीतों से गूंजने वाले खेत अब हो गए है बंजर
◆गांवों में पीछे छूट कई लोक-समृद्धि और पुरखों की विरासत
◆पलायन और बंजर खेतों ने छीन ली पहाड़ की कृषि संस्कृति
◆इतिहास के पन्नों में खो रही पहाड़ के गांवों की आत्मनिर्भरता

होती चली गई। अब मेहनत से खेती करने की बजाय बाजार से अनाज खरीदना आसान विकल्प माना जाने लगा है।

पहाड़ के गांवों से बैलों का गायब होना केवल कृषि संकट नहीं है। इसके साथ ही पहाड़ की सदियों पुरानी संस्कृति भी कमजोर हो रही है। हरेला, रोपाई, सामूहिक श्रम, गोठ संस्कृति, जैविक खेती और पारंपरिक बीजों की परंपरा धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। नई पीढ़ी बैलों से जुड़ी उस जीवनशैली को देख ही नहीं पा रही, जो कभी उत्तराखंड की पहचान थी।

आने वाले समय में पहाड़ के अधिकांश गांवों में बैलों की जोड़ी केवल तस्वीरों और लोकगीतों में ही दिखाई देगी। आज भी कुछ गांवों में कोई बुजुर्ग अपनी बैलों की जोड़ी के साथ खेत जोतता दिखाई देता है। वह केवल अपनी जमीन नहीं जोत रहा होता, बल्कि एक पूरी परंपरा को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद क्या होगा? क्या अगली पीढ़ी फिर कभी हल और बैलों के साथ खेत में उतरेगी, या पहाड़ की खेती इतिहास बनकर रह जाएगी?

पहाड़ के गांवों में घटती बैलों की संख्या केवल एक सांख्यिकीय बदलाव नहीं, बल्कि उस सामाजिक परिवर्तन का संकेत है जिसमें पलायन, बदलती अर्थव्यवस्था, घटती खेती और बंजर होते खेत मिलकर पहाड़ की आत्मा को धीरे-धीरे खोखला कर रहे हैं। 25-30 वर्ष पहले अधिकांश गांवों में बैलों की कई जोड़ियां होती थीं। आज अनेक गांवों में एक भी बैल नहीं बचा। खाली पड़े खेतों में झाड़ियां और जंगल तेजी से फैल रहे हैं। जंगली जानवर खेती छोड़ने की बड़ी वजह बन रहे हैं। गोठ खाली हैं, पशुपालन लगातार घट रहा है। खेती के साथ लोक संस्कृति और सामुदायिक जीवन भी कमजोर पड़ रहा है। जिस दिन पहाड़ के गांवों से आखिरी बैलों की जोड़ी भी खत्म हो जाएगी, उस दिन केवल एक कृषि परंपरा नहीं टूटेगी, बल्कि पहाड़ की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।

ग्रामवासियों को बिल देकर पैसा भी वसूला जा रहा है: अग्रवाल

संवाददाता

देहरादून। देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि दो वर्षों से पानी की सप्लाई लोगों को दी जा रही है एवं जल निगम जल संस्थान द्वारा ग्रामीण वासियों को बिल देकर पैसा भी वसूला जा रहा है।

देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्यालय चंदननगर देहरादून में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सचिव पेयजल, उत्तराखंड शासन से मुलाकात करने के बाद रखी गई। बैठक की अध्यक्षता देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने की। संस्था के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि ठेकेदारों को 2 वर्षों से लगातार सचिवालय, एस डब्लू एस एम कार्यालय एवं जल निगम, जल संस्थान के चक्कर काट-काट कर पैर घिस गए एवं थक चुके हैं फिर भी धन आवंटित न होने एवं प्रति माह आश्वासन से परेशान होकर सचिव के आगे गुहार लगाई गई कि उनकी एसोसिएशन के पांच सदस्यीय दल को मुख्यमंत्री/ पेयजल मंत्री से मुलाकात कराकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगा है। अमित अग्रवाल ने कहा क्योंकि संगठन के ठेकेदारों में अत्यधिक रोष पैदा हो चुका है एवं बताया गया है कि ठेकेदारों या योजनाओं के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है उसका पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और अधिकारियों की होगी। ठेकेदारों ने पूर्ण रखरखाव संचालन एवं अनुरक्षण करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा जल जीवन मिशन ने ठेकेदारों का उनके साथ जुड़े मजदूर परिवारों सप्लायरों का जीवन समाप्त कर दिया है।

संस्था के अध्यक्ष अमित अग्रवाल कहा कि सरकार द्वारा पैसा देने की मंशा नहीं प्रतीत होती है लगातार सरकार द्वारा पहले के एम एल फाइल बनाना, आर पी डब्लू एस एस आई डी बनाना, स्वजल आईडी, सुजलाम आईडी, एस एन ए पोर्टल बनाने के लिए बोला गया। इन सभी में ठेकेदारों ने पूर्ण सहयोग कर सरकार का साथ दिया और वैसे ही किया परंतु स्पर्श पोर्टल पर आज तक कोई भी योजनाओं का रूपरेखा नहीं दिखाई दी। यहां तक की भारत सरकार से तीन माह पूर्व 32 करोड रुपए आज तक सरकार खर्च नहीं कर पाई है क्योंकि भारत सरकार के स्पर्श पोर्टल पर जल जीवन मिशन की योजना दिख नहीं रही हैं। जहां उत्तराखंड राज्य में 2000 करोड रुपए ठेकेदारों को बकाया राशि देनी है। इस सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि भुगतान नहीं करना या जानबूझकर पेमेंट रोकना है। उत्तराखंड राज्य में करोड रुपए जल जीवन मिशन के योजनाओं पर खर्च हो चुके हैं, वह अब बर्बाद होती हुई दिख रही है, इसमें सरकार और अधिकारी अपने ठीकरा ठेकेदारों पर पेनल्टी और ब्लैकलिस्ट करने के रूप में थोप रहे हैं। जिससे ठेकेदारों का कोई दोष नहीं है। बीते दिनों देहरादून के डीएम द्वारा जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है जिसमें सरकार खुद ही अपने सवालों के घेरे में पाए गए हैं। अमित अग्रवाल ने बताया कि जो काम बकाया हैं उसमें ज्यादातर वन भूमि एवं नेशनल हाईवे की स्वीकृति को बताया गया है एवं समय से ठेकेदारों का भुगतान न होना मुख्य कारण भी है।

क्या डैंड्रफ ही खुजलीदार स्कैल्प की वजह है? जानें 5 अन्य कारण

स्कैल्प यानी खोपड़ी में खुजली का मतलब हमेशा डैंड्रफ नहीं होता। कई बार इसके पीछे अलग-अलग कारण होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि खुजली के पीछे किन-किन कारणों का हाथ हो सकता है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इससे आप सही कारण जानकर बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे और समस्या से राहत मिल सकेगी।

बालों की रूखी प्रकृति : अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सूखे हैं, तो इससे खोपड़ी में खुजली हो सकती है। बालों में नमी की कमी होने पर सिर की त्वचा भी सूख जाती है, जिससे खुजली होने लगती है।

इस समस्या से राहत पाने के लिए हफ्ते में दो बार तेल मालिश करें।

इसके अलावा नमी देने वाले शैंपू का इस्तेमाल करें और कंडीशनर भी लगाएं ताकि बालों को नमी मिल सके और सिर की त्वचा स्वस्थ रहे।

एलर्जी का प्रभाव: कभी-कभी नए हेयर केयर प्रोडक्ट्स या किसी खाने की चीज से एलर्जी होने पर भी खोपड़ी में खुजली हो सकती है।

अगर आपने हाल ही में कोई नया शैंपू या कंडीशनर इस्तेमाल किया हो या फिर किसी नई चीज का सेवन किया हो तो यह समस्या हो सकती है।

इसके लिए सबसे पहले यह पता लगाएं कि आपको किस चीज से एलर्जी है और उसे अपने जीवनशैली से दूर रखें।

धूप का असर: गर्मियों में तेज धूप भी खोपड़ी की खुजली का कारण बन सकती है। धूप की वजह से सिर की त्वचा जल सकती है या फिर उसमें जलन हो सकती है, जिससे खुजली होने लगती है।

इसके लिए अपने सिर को धूप से बचाने के लिए टोपी पहनें या फिर स्कार्फ बांधें।

इसके अलावा सुबह या शाम के समय बाहर निकलें जब धूप कम तेज हो। इससे आपकी खोपड़ी सुरक्षित रहेगी और खुजली की समस्या भी कम होगी।

मानसिक तनाव: तनाव भी खोपड़ी की खुजली का एक अहम कारण हो सकता है। जब हम तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे सिर की त्वचा भी प्रभावित होती है।

इस समस्या से राहत पाने के लिए ध्यान, योग या फिर गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें।

इसके अलावा अपनी दिनचर्या में थोड़ी शांति और आराम शामिल करें ताकि आपका मन शांत रहे और तनाव कम हो सके।

त्वचा के रोग: कुछ त्वचा संबंधी रोग जैसे सोरियासिस या एक्जिमा भी खोपड़ी की खुजली का कारण बन सकते हैं। इन रोगों में त्वचा पर खुजली, सूजन और लालिमा होती है, जिससे सिर की त्वचा भी प्रभावित होती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें और उचित इलाज करवाएं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि खुजलीदार खोपड़ी हमेशा डैंड्रफ ही नहीं होती बल्कि इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।

प्राकृतिक और जैविक स्किन केयर उत्पादों का उपयोग करने से मिल सकते हैं ये फायदे

आजकल बाजार में प्राकृतिक और जैविक स्किन केयर उत्पादों की भरमार है। ये उत्पाद न केवल त्वचा की देखभाल करते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। इनका उपयोग करने से त्वचा को प्राकृतिक पोषण मिलता है और हानिकारक रसायनों से बचाव होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि प्राकृतिक और जैविक स्किन केयर उत्पादों का उपयोग कैसे फायदेमंद हो सकता है और इन्हें अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जा सकता है।

रसायनों से मुक्त होते हैं : प्राकृतिक और जैविक स्किन केयर उत्पादों में हानिकारक रसायनों की मात्रा बहुत कम होती है या बिलकुल नहीं होती। इससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचने का खतरा नहीं रहता।

रसायनों वाले उत्पादों से त्वचा पर जलन, खुजली या एलर्जी हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक और जैविक उत्पादों का चयन करना बेहतर होता है।

ये उत्पाद आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखते हैं, जिससे आपकी त्वचा चमकदार और निखरी हुई दिखती है।

पर्यावरण के लिए अनुकूल : प्राकृतिक और जैविक स्किन केयर उत्पाद पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता।

इसके अलावा इन उत्पादों के निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करता है।

ये उत्पाद आसानी से प्रकृति में घुल जाते हैं और इनके अपशिष्टों को प्रकृति द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है।

त्वचा को प्राकृतिक पोषण : प्राकृतिक और जैविक स्किन केयर उत्पाद आपकी त्वचा को प्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं।

इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे गुण होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। इन उत्पादों का नियमित उपयोग करने से आपकी त्वचा की चमक बढ़ती है और वह निखरी हुई दिखती है।

इसके अलावा ये उत्पाद त्वचा की प्राकृतिक नमी को बनाए रखते हैं, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार दिखती है।

मंत्री की 'चौखट' पर युवाओं की 'चीख'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में विरोध-प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। धरने होते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, नारे लगते हैं और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन जब किसी मंत्री के सरकारी आवास के बाहर युवा आत्महत्या का प्रयास करने पर मजबूर हो जाएं, तब यह केवल एक प्रदर्शन नहीं रह जाता। यह उस व्यवस्था पर आरोप-पत्र बन जाता है, जो युवाओं को उम्मीद देने के बजाय निराशा की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अचानक उस समय गंभीर मोड़ पर पहुंच गया, जब कुछ अभ्यर्थियों ने आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन सवाल वहीं रह गया क्या उत्तराखंड का युवा अब अपनी बात सुनाने के लिए जान दांव पर लगाने को मजबूर हो रहा है? यह दृश्य केवल एक विभाग की भर्ती का नहीं था। यह उन हजारों युवाओं की बेचैनी का प्रतीक था, जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं, परिणामों और नियुक्तियों के बीच अपनी उम्र और उम्मीदें गंवा रहे हैं।

राजनीति अक्सर कहती है कि उत्तराखंड युवाओं का राज्य है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह युवाओं के अवसरों का भी राज्य है? नर्सिंग अभ्यर्थी सड़क पर इसलिए नहीं हैं कि उन्हें राजनीति करनी है। वह इसलिए सड़क पर हैं क्योंकि उनके हाथों में डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं। उन्होंने पढ़ाई की, प्रशिक्षण लिया, परीक्षाएं दीं और अब नियुक्ति की उम्मीद में सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं। जब दरवाजे नहीं खुले तो वह मंत्री के आवास तक पहुंच गए। सरकार की भी अपनी दलील हो सकती है। भर्ती प्रक्रियाओं के अपने नियम हैं, प्रशासनिक बाधाएं हैं, वित्तीय सीमाएं हैं। लेकिन लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल नियम गिनाना नहीं, बल्कि संवाद कायम रखना भी है। यदि युवा यह महसूस करने लगें कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, तो असंतोष गहराता है।

उत्तराखंड में यह पहला अवसर नहीं है जब भर्ती से जुड़े मुद्दों ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया हो। पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक, नियुक्तियों में देरी और रिक्त पदों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हर बार सरकार ने कार्रवाई और सुधार का भरोसा दिया। लेकिन जब

◆अब हक मांगने के लिए जान दांव पर लगाने को मजबूर हो गया है उत्तराखंड का युवा
◆स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर नर्सिंग अभ्यर्थियों की बेबसी है व्यवस्था का आरोप-पत्र
◆उत्तराखंड में धरने और नारों से भी अब आगे बढ़ गया है नर्सिंग अभ्यर्थियों का आक्रोश
◆प्रतियोगी परीक्षाओं के फेर में उम्र और सपने गंवाते प्रदेश के युवाओं का फूट गया गुस्सा

फिर कोई समूह सड़क पर बैठा दिखाई देता है, तो यह संकेत देता है कि समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि विरोध का स्वर अब केवल नारों तक सीमित नहीं रह गया। जब कोई युवा आत्महत्या जैसा कदम उठाने की कोशिश करता है, तो यह केवल व्यक्तिगत निराशा नहीं होती यह व्यवस्था के प्रति गहरे अविश्वास का संकेत भी हो सकता है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह मुद्दा आने वाले समय में सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। विपक्ष निश्चित रूप से इसे बेरोजगारी, रिक्त पदों और युवाओं की उपेक्षा से जोड़कर सरकार पर हमला करेगा। कांग्रेस पहले ही रोजगार और भर्ती के मुद्दों को लगातार उठा रही है। यदि ऐसे घटनाक्रम बढ़ते हैं, तो यह केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संकट भी बन सकते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। केवल सरकार को घेरना पर्याप्त नहीं है। युवाओं की समस्याओं का समाधान केवल प्रेस कान्फ्रेंस और धरनों से नहीं निकलेगा। सत्ता और विपक्षकृदोनों को भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और विश्वसनीय बनाने पर गंभीर पहल करनी होगी।

उत्तराखंड के पहाड़ों से हर साल हजारों युवा रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर जाते हैं। जो यहीं रहकर सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, यदि वही निराशा में डूबने लगें, तो यह किसी भी सरकार के लिए गंभीर चेतावनी है। स्वास्थ्य विभाग की विडंबना भी कम नहीं है। एक ओर अस्पतालों में स्टाफ की कमी की चर्चा होती है, दूसरी ओर प्रशिक्षित नर्सिंग अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। यदि जरूरत और उपलब्ध मानव संसाधन के बीच संतुलन नहीं बन पा रहा, तो यह नीति-निर्माण पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अब सरकार के सामने दो रास्ते हैं। पहलाकृइस घटना को एक सामान्य प्रदर्शन मानकर भूल जाए। दूसरा इसे एक चेतावनी की तरह ले और संवाद, पारदर्शिता तथा समयबद्ध निर्णय के जरिए युवाओं का भरोसा लौटाने की कोशिश करे। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी सफलता केवल योजनाएं बनाना नहीं होती, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि उसके राज्य का कोई युवा अपने भविष्य के लिए इतना निराश न हो जाए कि उसे जीवन समाप्त करने का विचार आए।

उत्तराखंड को इस घटना को केवल एक विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक चेतावनी के रूप में देखना होगा। क्योंकि जिस राज्य का युवा उम्मीद छोड़ने लगे, वहां केवल नौकरियां नहीं, भरोसा भी संकट में पड़ जाता है।

शब्द सामर्थ्य -099

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. भारत के वर्तमान वित्तमंत्री 6. हित, उपकार 7. असमान, पूर्वोत्तर का एक राज्य 8. किसी वस्तु व्यक्ति आदि के पहचान सूचक संबोधन का शब्द, संज्ञा 10. शवस्थल पर बनाया गया मकान, योग का अंतिम अंग, तपस्या 13. इंकार करना, ना कहना 14. पिता, क्लर्क, सम्मानीय व्यक्ति 15. आय पर लगने वाला टैक्स, इंकमटैक्स 16. प्रतिद्वंद्वी, प्रेमिका का दूसरा प्रेमी 17. परंपरा, रीति, रिवाज 20. रुप से युक्त, चिह्न, लक्षण, नाटक, एक साहित्यिक अलंकार 23. लोग, प्रजा 25. नामी, नामवर, प्रसिद्ध 27. संसार का स्वामी, बादशाह, सम्राट, ईश्वर 28. फैलाना, खिंचाव पैदा करना।

ऊपर से नीचे

1. मारना, प्रहार करना, आघात करना 2. मिथ्याअभिमान, आडंबर 3. विपत्ति, आफत 4. मालदार, धनवान, अमीर 5. ज्ञान प्राप्त करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना 7. हक 9. विवश, लाचार 11. मानकंद, नापने का पैमाना 12. अपमानित और तिरस्कृत 17. संतान उत्पन्न करने की क्रिया, जन्म देने की क्रिया 18. लंबे कपड़े का गट्ठा, पशुओं को रखने की जगह 19. जलयान, वायुयान, जलपोत 21. आश्रय, सहारा 22. थोड़ा, जरा, तनिक 24. जुर्म, गुनाह 26. बाघ की तरह का धारीदार हिंसक एवं विशाल पशु।

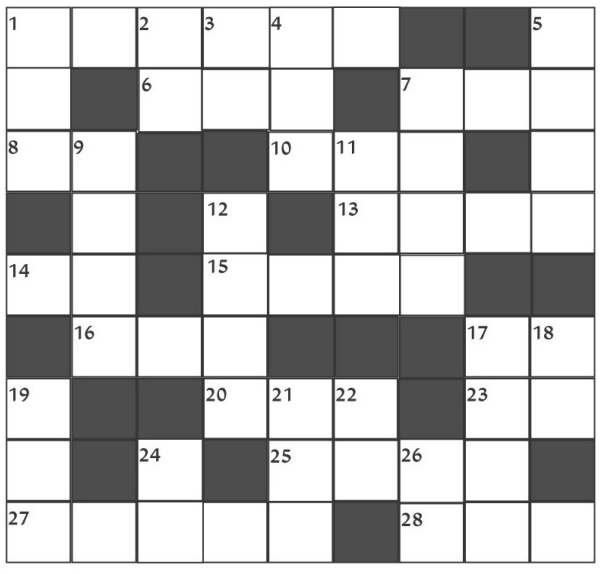

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 98 का हल

भू	कं	प	■	फा	य	दा	■	स
प	■	ल	ला	ट	■	य	ती	म
ति	ल	क	■	क	न	क	■	झ
■	क्ष्म	■	■	■	रे	■	■	■
ग	ण	क	■	सं	श	य	■	सौ
ह	■	या	च	क	■	म	न्न	त
रा	क्ष	स	■	र	क्ष	क	■	न
■	त्रि	■	■	■	मि	■	■	■
शा	य	री	■	का	त	र	■	गो

प्रेग्नेंसी की वजह से हर 20 मिनट में 1 किशोरी की होती है मौत

दुनियाभर में प्रेग्नेंसी या बच्चे को जन्म देने के दौरान हर 20 मिनट में 1 टीनएज बच्ची की मौत हो जाती है। यह नए आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि दुनियाभर में 15 से 19 साल की टीनएज लड़कियों की मौत का सबसे बड़ा कारण प्रेग्नेंसी है। प्रेग्नेंसी या बच्चे को जन्म के दौरान होने वाली जटिलताओं की वजह से हर साल करीब 30 हजार टीनएज लड़कियों की मौत हो जाती है। इनमें से ज्यादातर गरीब परिवार और ग्रामीण इलाकों की होती हैं। एनजीओ की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि प्रेग्नेंसी से जुड़ी समस्याओं जैसे ब्लीडिंग, ब्लड पॉइजनिंग, लेबर के दौरान अवरोध, असुरक्षित गर्भपात की वजह से होने वाली जटिलताएं, दुनियाभर में टीनएज लड़कियों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। यह खतरा सिर्फमां के लिए नहीं बल्कि होने वाले बच्चे के लिए भी है। आंकड़े बताते हैं कि टीनएज माताओं से जन्म लेने वालों नवजात बच्चे की भी मृत्यु का खतरा अधिक उम्र की माताओं से जन्म वाले बच्चों की तुलना में अधिक होता है। 20 साल से कम उम्र की मां से जन्म लेने वाले बच्चे की मौत का खतरा 20 साल से अधिक उम्र की मां से जन्मे बच्चे की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक होता है।

हालांकि दुनियाभर में साल 1990 के बाद से प्रेग्नेंसी और बच्चे को जन्म देने के दौरान होने वाली मौतों का आंकड़ा कम हुआ है। बावजूद इसके कई देशों में अब भी हजारों टीनएज लड़कियां हर साल जबरन हुई शादी या रेप की वजह से समय से पहले मां बन जाती हैं। नाइजीरिया, डिमेब्रैटिक रिपब्लिक ऑफकांगो, मलावी और तन्जानिया जैसे देशों की गरीब लड़कियों को तो गर्भनिरोधक तक नहीं दिया जाता।

एनजीओ की किर्स्टी मेकनील कहती हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि हर साल इतनी युवतियों की मौत सिर्फइसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें गर्भनिरोधक जैसे कॉडम या दवाएं नहीं दी जाती। फिर चाहे इसकी वजह सांस्कृतिक दीवारें हों या फिर काल्पनिक बातें।

यूके ने इस खतरनाक अवरोधों को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया है ताकि दुनियाभर की महिलाओं और लड़कियों के पास इस बात का अधिकार हो कि उन्हें कब और कैसे प्रेग्नेंट होना है। एक निर्णय जो उनकी जान बचा सकता है। मेकनील कहती हैं श्लेकिन यह साफहै कि अभी इस मामले में और काम करने की जरूरत है। लड़कियों के लिए गर्भनिरोधक की पहुंच बढ़ानी होगी और उसे मुफ्त में बांटना होगा। साथ ही हमें फैमिली प्लानिंग से जुड़ी झूठी और काल्पनिक बातों को भी दूर कर लड़कियों को जागरूक करना होगा ताकि वे फैसला कर सकें कि उनके अपने शरीर के साथ क्या होगा।

गर्भावस्था में रखें आहार का ख्याल

गर्भावस्था ऐसा समय है जब मां को अच्छे पोषण की जरूरत होती है। इस दौरान सही पोशण बच्चे के विकास और मां के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है। माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उनके पोशण में विटामिन और मिनरल्स की कमी न हो। गर्भावस्था के दौरान सही डायट चार्ट बनाना और उसका पालन करना जरूरी है।

गर्भावस्था के दौरान आप जो भी आहार लेती हैं, उससे न केवल आपके शरीर को पोशण मिलता है, बल्कि आपके पेट में पल रहे बच्चे का भी विकास होता है। हर दिन के साथ आपकी जरूरत बडती जाती है।

आपको हर प्रकार का भोजन अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इससे आपके लिए यह ध्यान में रखना आसान हो जाता है कि आप क्या खा रही हैं। भोजन में तभी जरुरी विटामिन संतुलित मात्रा में शामिल हों। जंक फूड के सेवन से बचें क्योंकि इससे बेवजह आपका वजन बडेगा और पोशक पदार्थों की कमी होगी।

आमतौर पर हमारे देश में गर्भावस्था के दौरान ऐसा खाना खाने की सलाह दी जाती है, जो बहुत सारे घी में बना हो हालांकि इस तरह के आहार के अपने फायदे हैं, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। नहीं तो वजन तेजी से बडता है और बच्चे के जन्म के बाद वजन कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दौरान सक्रिय रहें और सेहतमंद आहार लें।आपके आहार में सभी समूहों के पोशक पदार्थ शामिल होने चाहिए जैसे काबोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन व मिनरल्स और डेयरी उत्पाद।

गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं को बहुत ज्यादा भूख लगती है और ज्यादातर महिलाएं भूख लगने पर जंक फूड और अस्वास्थ्यप्रद आहार खाना चाहती हैं। ऐसे भोजन में काबोहाइड्रेटध् वसा तो भरपूर मात्रा में होते हैं लेकिन पोशक पदार्थो की कमी होती है। ऐसे में अपने आहार पर ध्यान देना जरूरी है।

इसी तरह अगर आपको कोई भोजन अच्छा नहीं लग रहा, जो आपकी सेहत और बच्चे के विकास के लिए जरूरी है तो अपने डायटीशियन से बात कर इसका कोई विकल्प लें ताकि आपकी पोशण संबंधी सभी जरूरतें पूरी हो सकें.

दिन में दो से तीन बार भरपेट खाने के बजाए कम मात्रा में बार-बार खाएं. इससे पाचन की समस्या भी नहीं होगी। इसके अलावा नियमित रूप से थोडा बहुत व्यायाम करें, जिससे शरीर में हॉर्मोनों का संतुलन बना रहेगा और आप गर्भावस्था के दौरान फिट और तरोताजा बनी रहेंगी।

श्वेता तिवारी ने रेड ड्रेस में बिखेरा जलवा

श्वेता तिवारी सिर्फ एक एक्टिव और टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं. उनके फैशन सेंस में सिंपल और एलिगेंट का परफेक्ट मिक्स नजर आता है जो हर मौके पर उनके लुक को परफेक्ट बनाता है. चाहे रैड कार्पेट हो या कैजुअल आउटिंग, श्वेता हमेशा अपनी स्टाइल और ग्रेस से लोगों को इंप्रेस करती हैं. उनके इस इंस्टाग्राम पोस्ट में भी ये साफ दिखाई देता है कि वो फैशन और परफॉर्मेंस दोनों में बराबर एक्सील करती हैं.

श्वेता तिवारी हमेशा से ही अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए फैंस के बीच काफी पॉपुलर रही हैं. इस इंस्टाग्राम पोस्ट में उनका लुक देखते ही बनता है. श्वेता रेड कलर की लेयर्ड ड्रेस में नजर आ रही हैं जो उनके स्टाइल और ग्रेस को और निखार रही है. ड्रेस की फ्लोइंग लेयर्स उनके मूवमेंट के साथ खूबसूरती से झूल रही हैं और उनका सिंपल लेकिन एलिगेंट स्टाइल उन्हें मॉडर्न और क्लासिक दोनों तरह का लुक दे रहा है. उन्होंने अपने लुक को गोल्डन ईयररिंग्स और पेस्टल हील्स के साथ कंप्लीट किया है जो उनकी पर्सनालिटी को और हाईलाइट कर रहे हैं. उनके बाल खुले और सॉफ्ट वेव्स में सेट हैं, जो उनके चेहरे की खूबसूरती को और निखारते हैं. उनके नेचुरल पोज ने तस्वीर को और भी खास बना दिया है. वर्क फ्रंट की बात करें तो श्वेता तिवारी ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में की थी और धीरे-धीरे खुद को टॉप टीवी एक्ट्रेस बन गई थी.

उन्हें सबसे ज्यादा पहचान कसौटी जिंदगी की की प्रेरणा के रूप में मिली, जहां उन्होंने प्रीति का रोल निभाया। इसके अलावा श्वेता ने कई रियलिटी शो जैसे कि खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा में नजर आई थी. टीवी सीरियल्स के अलावा, उन्होंने वेब शोज और प्रिंट कमर्शियल्स में भी अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है. उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही नेचुरल और दिल को छू लेने वाली रही है जिससे फैंस उनके हर प्रोजेक्ट में जुड़े रहते हैं.

ऑटिज्म बीमारी नहीं, समझ और अपनापन चाहिए, ईशा सिंह ने समाज की सोच पर उठाए सवाल

टीवी अभिनेत्री ईशा सिंह इन दिनों अपने आने वाले शो जूही मुई को लेकर चर्चा में हैं। इस शो में वह अपने करियर का अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने जा रही हैं। ईशा इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर रहने वाली लड़की जूही की भूमिका में नजर आएंगी। अपने इस किरदार की तैयारी और ऑटिज्म को लेकर समाज में फैली गलतफहमियों पर अभिनेत्री ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में लोग ऑटिज्म को बीमारी समझते हैं, जबकि यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। ईशा सिंह ने कहा, आज भी बहुत से लोग ऑटिज्म को सही तरीके से नहीं समझते। जागरूकता की कमी पढ़े-लिखे लोगों के बीच भी देखने को मिलती है। मेरे अपने दोस्तों में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म के बारे में सही जानकारी नहीं है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि लोग इस विषय को समझें और इसके बारे में सही जानकारी हासिल करें।

ईशा सिंह ने कहा, ऑटिज्म को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे बीमारी मान लेते हैं। जबकि सच यह है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि मस्तिष्क के विकास से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। कुछ माता-पिता यह सोचते हैं कि ऑटिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जबकि यह पूरी तरह गलत धारणा है। ऑटिज्म न तो संक्रामक है और न ही यह किसी तरह की बीमारी है। अभिनेत्री का कहना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर रहने वाले बच्चे अक्सर बेहद बुद्धिमान, संवेदनशील और प्यार करने वाले होते हैं। उन्हें समाज से सहानुभूति नहीं बल्कि समझ और स्वीकार्यता की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग पहचान और विशेषताओं के साथ दुनिया में आता है। अपने नए शो में निभाए जा रहे किरदार को लेकर ईशा सिंह ने कहा, यह मेरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी भरा रोल है। चूंकि यह एक बेहद संवेदनशील विषय है, इसलिए मैंने इसकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा उद्देश्य ऑटिज्म से जुड़े लोगों की भावनाओं और व्यवहार को पूरी ईमानदारी के साथ दर्शकों तक पहुंचाना था। अभिनेत्री ने बताया, जूही के किरदार के लिए मुझे अपने चलने, बोलने, बैठने, प्रतिक्रिया देने और भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके पर भी बारीकी से काम करना पड़ा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर रहने वाले लोग हर भावना को गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उसे सामान्य तरीके से व्यक्त कर पाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने अभिनय में किसी तरह का दिखावा नहीं रखा, बल्कि छोटे-छोटे हाव-भाव और स्वाभाविक अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया। ईशा सिंह ने कहा, मुझे विश्वास है कि जब दर्शक जूही मुई देखेंगे तो उन्हें मेरे किरदार की कई ऐसी बारीकियां नजर आएंगी, जिन पर पूरी टीम ने काफी मेहनत की है।

डीएम ने प्रथम गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

हमारे संवाददाता

चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जनपद चम्पावत में संचालित महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आज छमानिया स्थित निर्माणाधीन गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

लगभग 257 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने हॉस्टल ब्लॉक, टाइप-2 एवं टाइप-3 आवासीय ब्लॉकों, वॉलीबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, मल्टीपर्पस हॉल सहित विभिन्न खेल अधोसंरचनाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों तथा शेष कार्यों की चरणबद्ध कार्ययोजना की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों, अभियंताओं एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्येक कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी लोहाघाट नीतू डागर, प्रोजेक्ट मैनेजर केशव महाराज सिंह सहित कार्यदायी संस्था के अधिकारी, अभियंता एवं अन्य संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।

सू- दोकू क्र.099

	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.98 का हल

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1

शांत उत्तराखंड में 'उबल' रही है सियासत

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति ऊपर से जितनी शांत दिखाई देती है, भीतर उतनी ही बेचैन है। सचिवालय से लेकर सत्ता के गलियारों तक, भाजपा कार्यालय से लेकर कांग्रेस भवन तक, हर जगह एक ही चर्चा है 2027 की लड़ाई किस मुद्दे पर लड़ी जाएगी? कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि भाजपा विकास, चारधाम, समान नागरिक संहिता, निवेश, बुनियादी ढांचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनावी आधार बनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता भी इसी दिशा में दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और सत्ता विरोधी माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं।

पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रिया, बेरोजगारी, छात्रों का आक्रोश और युवाओं के प्रदर्शन जैसे मुद्दों ने चुनावी बहस में जगह बनानी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर उठे इन सवालों की गूंज उत्तराखंड तक पहुंच रही है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यही निर्णायक चुनावी मुद्दे बनेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इन विषयों ने राजनीतिक चर्चा का दायरा बढ़ा दिया है। सत्ता विरोधी लहर हर चुनाव में एक स्वाभाविक राजनीतिक चुनौती होती है। भाजपा के सामने भी यह चुनौती है कि वह लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता का विश्वास कैसे बनाए रखे।

पार्टी के पक्ष में कुछ मजबूत आधार हैं संगठन की ताकत, केंद्र और राज्य की समन्वित राजनीति, कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी नेटवर्क और मुख्यमंत्री धामी की सक्रिय छवि। दूसरी ओर उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि रोजगार, भर्ती, पलायन, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्वतीय क्षेत्रों की मूलभूत समस्याएं जनता की प्राथमिकताओं में बनी हुई हैं। यदि विपक्ष इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता है, तो भाजपा को केवल उपलब्धियां गिनाने से आगे बढ़कर समाधान और संवाद दोनों पर जोर देना होगा। कांग्रेस के लिए यह अवसर भी है और परीक्षा भी। पार्टी को कई मुद्दे मिले हैं बेरोजगारी, भर्ती, महंगाई, पलायन और स्थानीय असंतोष। लेकिन

◆उत्तराखंड में विस चुनाव 2027 की जंग से पहले बदला चुनावी मौसम
◆सत्ता के सामने युवाओं के सवाल और विपक्ष के सामने भरोसे की चुनौती

केवल सरकार की आलोचना चुनाव नहीं जिताती। कांग्रेस को यह भी दिखाना होगा कि उसके पास शासन का स्पष्ट विकल्प और विश्वसनीय नेतृत्व है। यदि पार्टी केवल विरोध तक सीमित रहती है, तो उसका असर सीमित रह सकता है। लेकिन यदि वह ठोस नीति, संगठनात्मक एकजुटता और स्थानीय नेतृत्व के साथ मैदान में उतरती है, तो मुकाबला अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है।

उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दल लंबे समय से अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य गठन में उनकी ऐतिहासिक भूमिका रही, लेकिन चुनावी स्तर पर वह लगातार सीमित होते गए हैं। फिर भी, यदि स्थानीय मुद्दे जल, जंगल, जमीन, पलायन और पर्वतीय अस्मिता अधिक प्रमुखता से उभरते हैं, तो क्षेत्रीय दलों को कुछ क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिल सकता है। राज्य की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार से जुड़ी है। युवाओं की अपेक्षाएं केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं हैं। वह पारदर्शी भर्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निजी निवेश, स्थानीय रोजगार और उद्यमिता के अवसर भी चाहते हैं। यदि राजनीतिक दल इन आकांक्षाओं को गंभीरता से लेते हैं, तो चुनावी बहस का स्तर भी बदल सकता हैराजनीतिक शोर के बीच उत्तराखंड के मूल प्रश्न अब भी वहीं हैं। पलायन कब रुकेगा? सीमांत गांव कैसे आबाद होंगे? खेती और बागवानी को कैसे लाभकारी बनाया जाएगा? स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ तक कब पहुंचेंगी? शिक्षा और रोजगार के लिए युवाओं को राज्य छोड़ना कब बंद होगा? पर्यटन का लाभ स्थानीय समुदाय तक कैसे पहुंचेगा? इन सवालों का उत्तर किसी एक चुनावी भाषण से नहीं मिलेगा। इनके लिए दीर्घकालिक नीति और राजनीतिक इच्छाशक्ति दोनों की आवश्यकता है।

यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि 2027 का चुनाव किस दल के पक्ष में जाएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि यह चुनाव केवल नारों का नहीं होगा। जनता विकास भी देखेगी, रोजगार भी पूछेगी। कल्याणकारी योजनाएं भी याद रखेगी, स्थानीय समस्याएं भी। नेतृत्व भी परखेगी और उम्मीदवार भी। उत्तराखंड आज एक ऐसे राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है जहां सत्ता के सामने विश्वास बनाए रखने की चुनौती है और विपक्ष के सामने विश्वसनीय विकल्प बनने की। 2027 की राह अभी लंबी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस बार चुनाव केवल सरकार बदलने या बचाने का नहीं होगा। यह इस बात की भी परीक्षा होगी कि कौन-सा राजनीतिक दल उत्तराखंड के पहाड़, युवाओं और भविष्य की आकांक्षाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझ और संबोधित कर पाता है।

अपर जिलाधिकारी ने तहसील एवं न्यायालय का किया निरीक्षण

हमारे संवाददाता

अल्मोड़ा। अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने गत दिवस तहसील कार्यालय अल्मोड़ा, उपजिलाधिकारी कार्यालय तथा न्यायालय का निरीक्षण कर विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने समस्त पटलों का निरीक्षण करते हुए पटल सहायकों को जनता से जुड़े कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा कार्यालयीन अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख-रखाव करने के निर्देश दिए।

उन्होंने खतौनियों को समय पर तैयार करने, कार्यालय को सुव्यवस्थित रखने, प्राप्त होने वाली जनसामान्य की डाक पर त्वरित कार्रवाई करने तथा न्यायालय की निस्तारित पत्रावलियों को नियमानुसार अभिलेखागार में अभिसंचित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक स्टाम्प वादों के 24 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 24,64,160 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 19 प्रकरणों का निस्तारण कर 31,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने कहा कि न्यायालयों का उद्देश्य लोगों में नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विधिक प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षित एवं मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना आवश्यक है तथा खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को एफएसएसएआई के नियमों का पालन करना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी संजय कुमार , स्टाम्प वादों के पेशकार योगेश तिवारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पेशकार मनोज काण्डपाल उपस्थित रहे।

सीटू ने एसएफआई के 26 जुलाई के विरोध प्रदर्शन को दिया समर्थन

संवाददाता

देहरादून। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 26 जुलाई के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया।

आज यहां सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) देहरादून ने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) उत्तराखंड राज्य समिति द्वारा 26 जुलाई 2026 को आयोजित किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास मार्च को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। सीटू ने जारी बयान में कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज कर उनकी लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास अत्यंत निंदनीय है। छात्रों द्वारा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर उठाई जा रही जायज मांगों का जवाब दमन और बल प्रयोग से देना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। सीटू ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रश्न केवल छात्रों के नहीं बल्कि पूरे समाज के मुद्दे हैं। इसलिए मजदूर आंदोलन छात्रों के इस संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा है। सीटू देहरादून ने अपने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा संबद्ध यूनियनों के सदस्यों से अपील की है कि वे 26 जुलाई (रविवार) प्रातः 11 बजे परेड ग्राउंड, देहरादून पहुँचकर एसएफआई के विरोध प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री आवास तक मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हों और छात्रों के लोकतांत्रिक संघर्ष को मजबूत करें। सीटू ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा तथा शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए छात्र, युवा, मजदूर, कर्मचारी और सभी जनवादी संगठनों की एकजुटता आज समय की आवश्यकता है। संगठन ने सभी लोकतंत्र पसंद नागरिकों से भी इस प्रदर्शन में भाग लेकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया।

ऊखीमठः मनसूना नदी की पुलिया के नीचे मिला शव, जांच शुरु

हमारे संवाददाता

रूद्रप्रयाग। ऊखीमठ स्थित मनसूना नदी की पुलिस के नीचे से आज सुबह एक शव बरामद होने पर सनसनी फैल गयी। सूचना मिलने पर पुलिस व डीडीआरएफ सहित सम्बन्धि विभागों के लोगों ने मौके पर पहुंच कर शव को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार आज सुबह जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, रुद्रप्रयाग को कॉलर भगत सिंह द्वारा सूचना दी गई कि ऊखीमठ ग्रामीण बैंक के समीप मनसूना नदी पर स्थित पुलिया के नीचे एक शव दिखाई दे रहा है।

सूचना प्राप्त होते ही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के निर्देश पर जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा तत्काल डीडीआरएफ टीम, तहसील ऊखीमठ प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंची डीडीआरएफ टीम ने आवश्यक रेस्क्यू कार्यवाही करते हुए शव को नदी से बाहर निकाला।

शव की पहचान ग्राम मनसूना, तहसील ऊखीमठ निवासी 48 वर्षीय नन्दन सिंह पंवार पुत्र स्वर्गीय इन्द्र सिंह पंवार के रूप में हुई है। जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु शव को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है।

लाठियों के खिलाफ 'खाकी' की बगावत

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

के इस सार्वजनिक इस्तीफे ने पूरे मामले को नया राजनीतिक और सामाजिक आयाम दे दिया है। यदि इस्तीफा औपचारिक रूप से संबंधित विभाग को सौंपा गया है, तो विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया और जांच भी चर्चा का विषय बन सकती है। जंतर-मंतर के मंच पर बैज उतारकर दिया गया यह इस्तीफा अब केवल एक प्रशासनिक घटना नहीं रह गया है। आंदोलन में शामिल युवाओं के लिए यह व्यवस्था के भीतर से उठी एक ऐसी आवाज बन गया है, जिसने उनके संघर्ष को नया नैतिक बल देने का काम किया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस आंदोलन और उससे जुड़ी भावनाओं को किस तरह संबोधित करती है। फिलहाल इतना तय है कि जंतर-मंतर के मंच से उतरा वह बैज देशभर में युवाओं के आंदोलन की सबसे चर्चित तस्वीरों में शामिल हो चुका है।

'दावे' बेमिसाल पर कटघरे में 'कंट्रोल'..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

प्रभावित कर सकते हैं। पेपर लीक का मामला केवल परीक्षा का नहीं, बल्कि विश्वास का संकट बन चुका है। यदि युवा यह महसूस करता है कि उसकी मेहनत सुरक्षित नहीं है, तो उसका असर सीधे मतदान पर पड़ सकता है। 2027 का चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला नहीं होगा। यह सरकार की प्रशासनिक विश्वसनीयता की भी परीक्षा होगी। क्या सरकार विवादित मामलों में समयबद्ध जांच पूरी कर पाएगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी? यही वह सवाल हैं, जिनका उत्तर जनता चुनाव से पहले जानना चाहेगी।

उत्तराखंड की राजनीति में कभी सड़क मुद्दा बनी, कभी पलायन, कभी गैरसैंण, कभी भू-कानून। अब ऐसा लगता है कि युवाओं का भविष्य और व्यवस्था की विश्वसनीयता भी उसी सूची में शामिल हो चुके हैं। यदि विपक्ष इन मुद्दों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सफल रहता है और सरकार समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं दिखा पाती, तो 2027 के चुनाव में विकास के साथ-साथ पेपर लीक, चढ़ावा और जवाबदेही भी बड़े चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार केवल अपने काम से नहीं, बल्कि संकट के समय अपनी जवाबदेही से भी आंकी जाती है।

राजनीति का 'माइक' ऑन, छात्रों की 'आवाज' म्यूट

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली। देश के अलग-अलग शहरों में एक जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। कहीं छात्र हाथों में तख्तियां लिए खड़े हैं, कहीं सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं। वह किसी एक राज्य के छात्र नहीं हैं। उनकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उनका प्रश्न एक है क्या मेहनत का कोई मूल्य बचा है? पेपर लीक का मामला अब किसी एक भर्ती परीक्षा का विवाद नहीं रह गया है। यह उस पीढ़ी की बेचैनी बन चुका है, जिसने बचपन से यही सुना कि पढ़-लिख लो, जिंदगी बदल जाएगी। अब वही पीढ़ी पूछ रही है कि अगर प्रश्नपत्र पहले ही बिक जाएगा, तो पढ़ाई किसके लिए करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सरकार कह रही है कि माफिया के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए सरकार पर लगातार हमलावर हैं। लेकिन इस पूरे राजनीतिक शोर के बीच सबसे कम सुनी जा रही आवाज उसी युवा की है, जिसके लिए यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है।

पेपर लीक की हर घटना के बाद एक तयशुदा क्रम दिखाई देता है। सरकार जांच की घोषणा करती है। विपक्ष प्रेस कान्फ्रेंस करता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगते हैं। कुछ गिरफ्तारियां होती हैं। फिर कुछ दिन बाद एक नया मामला सामने आ जाता है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि युवाओं का धैर्य पहले जैसा नहीं रहा। व केवल बयान नहीं सुनना चाहते। उन्हें परिणाम चाहिए। उनके लिए यह कोई टीवी डिबेट नहीं है। यह उनकी उम्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। एक भर्ती परीक्षा रद्द होने का मतलब सिर्फ नई तारीख नहीं होता। इसका मतलब है एक और साल की तैयारी, एक और साल का खर्च, परिवार पर बढ़ता आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव।

सरकार से सवाल है कि यदि पेपर लीक पर पहले भी कानून बने, एजेंसियां सक्रिय हुईं और गिरफ्तारियां हुईं, तो फिर बार-बार ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती हैं? लेकिन विपक्ष से भी सवाल कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब वह सत्ता में था, तब क्या परीक्षा प्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष थी? क्या आज का आक्रोश केवल सरकार बदलने का मुद्दा है या व्यवस्था बदलने का? युवा शायद इस राजनीतिक हिसाब-किताब में दिलचस्पी नहीं रखता। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रेस कान्फ्रेंस कौन कर रहा है। उसे फर्क इससे पड़ता है कि अगली परीक्षा

◆पेपर लीक पर देशभर में उबाल बरकरार, सरकार ने की सख्त कार्रवाई की बात
◆विपक्ष सरकार को घेर रहा, सवाल अब भी वही है युवाओं का भरोसा लौटेगा
◆सिस्टम का प्रश्नपत्र, युवाओं के सवाल, राजनीति के शोर में दबी वह आवाज

समय पर होगी या नहीं।

यह समझना होगा कि आज का प्रदर्शन केवल पेपर लीक के खिलाफ नहीं है। यह रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग भी है। देश का बड़ा युवा वर्ग वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। कई अभ्यर्थी उम्र सीमा के अंतिम पड़ाव पर हैं। कई परिवार अपनी बचत कोचिंग और रहने-खाने पर खर्च कर चुके हैं। जब ऐसी स्थिति में परीक्षा रद्द होती है या पेपर लीक की खबर आती है, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं रहती। यह सामाजिक और आर्थिक संकट भी बन जाती है। लोकतंत्र में जनता सरकार से असहमत हो सकती है, लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब जनता व्यवस्था पर ही विश्वास खोने लगे। आज कई युवाओं की सबसे बड़ी चिंता यही है। उन्हें लगने लगा है कि मेहनत और मेरिट से ज्यादा ताकत संगठित गिरोहों की हो गई है। यदि यह भावना गहरी होती गई, तो नुकसान केवल एक सरकार का नहीं होगा। नुकसान उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का होगा, जो समान अवसर देने का दावा करती है।

यह भी उतना ही स्पष्ट होना चाहिए कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन हिंसा उसका विकल्प नहीं हो सकती। यदि किसी आंदोलन की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, पुलिस पर हमला होता है या अराजकता फैलाने की कोशिश होती है, तो कानून को निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न हो। लोकतंत्र में डंडा और संवाद दोनों का अपना स्थान है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले कौन आता है।

आने वाले चुनावों में बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे युवाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। कभी जाति चुनाव का केंद्र होती थी, कभी धर्म। अब रोजगार और परीक्षा प्रणाली भी उसी सूची में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। सरकार के लिए यह केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वसनीयता का भी प्रश्न है। विपक्ष के लिए भी यह अवसर तभी है, जब वह केवल आरोप लगाने के बजाय ठोस वैकल्पिक व्यवस्था का खाका पेश करे।

इस समय देश की सड़कों पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, उसे केवल प्रदर्शनकारी भीड़ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उस भीड़ में कोई किसान का बेटा है, कोई रिक्शा चालक की बेटी, कोई पहाड़ के गांव से आया छात्र, कोई छोटे कस्बे का अभ्यर्थी। वह सरकार बदलने नहीं निकले हैं। वह अपना भविष्य बचाने निकले हैं और लोकतंत्र में जब युवा अपने भविष्य की सुरक्षा मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए, तब सबसे पहले राजनीतिक दलों को अपनी आवाज धीमी कर देनी चाहिए और युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। क्योंकि चुनाव पांच साल में एक बार आते हैं, लेकिन युवाओं की उम्र दोबारा नहीं आती।

विद्यालयों में 'स्वच्छता प्रतियोगिता दिवस' आयोजित

संवाददाता

देहरादून। नगर निगम में चलाये जा रहे स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान के चौथे दिन 'वेस्ट टू बेस्ट' विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

आज यहां नगर निगम द्वारा 20 जुलाई से 25 जुलाई तक 'स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान' संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यालयों में 'स्वच्छता प्रतियोगिता दिवस' आयोजित किया गया। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे के निर्देशनानुसार समस्त मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक ने अपने-अपने आवंटित विद्यालयों में अभियान का संचालन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए स्वच्छता विषयक प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालयों में चित्रकला, निबंध लेखन, भाषण, पोस्टर निर्माण, स्लोगन लेखन एवं 'वेस्ट टू बेस्ट' विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, कचरा पृथक्करण, प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली तथा संसाधनों के पुनः उपयोग के महत्व को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने आकर्षक पोस्टर, प्रभावशाली स्लोगन एवं प्रेरणादायक चित्रों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया तथा अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी सामग्री तैयार कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया तथा उन्हें अपने विद्यालय, घर एवं आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प दिलाया गया। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों से जोड़ना रहा। नगर निगम देहरादून द्वारा अभियान के अंतर्गत आगामी दिनों में भी विभिन्न गतिविधियों एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

जन समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध समाधान करें: धामी

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जन समस्या का संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित एवं सुशासन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही तभी सार्थक होगी, जब आम नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा शिकायतकर्ता को समाधान की प्रगति से भी अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार का दायित्व है। प्रत्येक अधिकारी जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए जनता की समस्याओं के समाधान में पूर्ण संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व का परिचय दें। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप एवं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को प्राप्त जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का समाधान जिला अथवा विभागीय स्तर पर संभव है, उनका तत्काल निस्तारण किया जाए तथा जिन प्रकरणों में उच्च स्तर पर निर्णय अपेक्षित है, उन्हें शीघ्र आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए, जिससे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समय पर न्याय एवं राहत मिल सके।

टीचर ने काटे छात्रों के बाल, ब्लेड से फाड़े कपड़े

हमारे संवाददाता

अल्मोड़ा। सल्ट क्षेत्र स्थित सरकारी इंटर कॉलेज (जीआईसी) बांगीधार में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भूगोल विषय की प्रवक्ता आरजू अफरोज अंसारी पर 12वीं कक्षा के पांच छात्रों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा है। आरोप है कि शिक्षिका ने अनुशासनहीनता के बहाने छात्रों के बाल कैंची से काट दिए, उनके गणवेश पर ब्लेड से वार किए और नोटबुक के पेज फाड़ दिए। घटना बीते बुधवार को हुई, जिसने पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर पैदा कर दी।

❑अभिभावकों ने प्रदर्शन कर की जांच की मांग
❑स्थानीय प्रशासन ने की जांच समिति गठित

प्रभावित छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि अनुशासन बनाए रखने के नाम पर बच्चों के साथ यह व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है। शिक्षिका ने न केवल शारीरिक रूप से छात्रों को ठेस पहुंचाई, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया। घटना की सूचना मिलते ही अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ता विद्यालय पहुंचे। उन्होंने शिक्षिका के कृत्य की कड़ी निंदा की और उनकी तत्काल बर्खास्तगी तथा दंड की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को कलंकित करता है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवक्ता आरजू अफरोज अंसारी ने प्रधानाचार्य राजेंद्र बगोरिया को लिखित माफी पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने भविष्य में ऐसी घटना न दोहराने का आश्वासन दिया। इसके बाद वह आवश्यक कार्य का हवाला देकर अवकाश पर चली गईं, जिससे विवाद और बढ़ गया।

वहीं स्थानीय एसडीएम रिंकू बिष्ट ने अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को देखते हुए तुरंत जांच समिति गठित कर दी है। समिति को सभी तथ्यों की बारीकी से जांच कर 26 जुलाई तक रिपोर्ट प्रधानाचार्य को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह ने बताया कि फिलहाल पीड़ित छात्रों के अभिभावकों की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है।

शान्ति व्यवस्था भंग करने का आरोपी हिरासत में

हमारे संवाददाता

पिथौरागढ़। शान्ति व्यवस्था भंग करने के आरोपी को जहां पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं फरार चल रहा वांरटी भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में लगातार गश्त एवं सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विगत दिवस कोतवाली धारचुला गेट के सामने सूरज सिंह धामी द्वारा हल्ला गुल्ला कर उत्पात मचाया हुआ था । पुलिस के समझाने पर भी वह नही मान रहा था बल्कि और अधिक उग्र हो रहा था। जिस पर पुलिस ने उसे बीएनएसएस की धारा 126/135/170 के तहत हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गयी है। वहीं कोतवाली पिथौरागढ़ से पुलिस द्वारा कोर्ट से प्राप्त चैक बाउंस मामले में गैर जमानतीय वारण्ट के अनुपालन में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत वारण्टी आरोपी रोहित राज को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस द्वारा चैकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने व सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले कुल 85 लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है।

सर्जरी के बाद युवक की मौत, परिजनों का हंगामा

संवाददाता

देहरादून। निजी चिकित्सालय में सर्जरी के बाद युवक की मौत पर परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

मिली जानकारी के अनुसार एक निजी चिकित्सालय में सर्जरी के बाद एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद उन्हें बताया गया था कि सर्जरी सफल रही है और मरीज की हालत सामान्य है, लेकिन देर रात अस्पताल की ओर से अचानक मरीज की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी गई। इसके कुछ समय बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध जताते हुए इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कुछ अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच की जाएगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता लग सकेगा।

डीएम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्राम प्रधानों को सौंपे बुशकटर

हमारे संवाददाता

पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व तथा आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक के मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में जनपद पौड़ी गढ़वाल में एक नई पहल की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपदा मद से खरीदे गए बुशकटर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि बरसात के दौरान झाड़ियों की समयबद्ध सफाई कर आपदा जोखिम को कम किया जा सके।

❑आपदा जोखिम कम करने में मिलेगी मदद

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने आज जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को बुशकटर वितरित किए। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में जनपद की 55 ग्राम पंचायतों को बुशकटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम प्रधानों को मौके पर ही बुशकटर सौंपे गए, जबकि अन्य प्रधान संबंधित तहसीलों से इन्हें प्राप्त कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों एवं ग्राम प्रधानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आगामी चरणों में अन्य ग्राम पंचायतों को भी इस पहल से जोड़ा जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात के मौसम में सड़कों, संपर्क मार्गों, पैदल रास्तों, सार्वजनिक स्थलों तथा जल निकासी मार्गों के किनारे झाड़ियां तेजी से बढ़ जाती हैं, जिससे आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्यों में भी कठिनाई आती है। समय पर झाड़ियों की कटान से दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी तथा आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य अधिक सुगमता से संचालित किए जा सकेंगे।

इस अवसर पर जिला पंचायतीराज अधिकारी जितेंद्र कुमार, सहायक जिला पंचायतीराज अधिकारी प्रदीप सुन्दरियाल, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश काला सहित संबंधित अधिकारी एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।